हिंन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

पृष्ठ संख्या.... 2

❒ वर्ष-9 ❒ अंक-3 जयपुर, शनिवार 1 फरवरी, 2025 ❒ एक प्रति 5 रुपये ❒ कुल पृष्ठ-4

बांदीकुई:- करोड़ों की जमीन का सरकारी दरो से कई गुना ज्यादा में हो रहा सौदा

सरकार बेफिक्र, पारिवारिक विवाद के चलते संपत्ति खुर्द-बुर्द करने पर भूमाफिया हावी

दौसा। बांदीकुई में करोड़ों रुपये की जमीनों पर अवैध कब्जा और उनकी खरीद-फरोख्त का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भूमाफिया सरकारी और निजी संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाकर उन्हें ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, जबकि सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बने हुए हैं।

कुछ समय पूर्व भी बांदीकुई में विवादित जमीन पर अवैध कब्जा और बिक्री की घटनाएं सामने आई थी। उदाहरण के लिए, अगस्त 2024 में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने रेलवे की लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। कोर्ट के आदेश पर जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची, तो स्कूल प्रशासन ने बच्चों को आगे कर पथराव किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

अंग्रेजों के जमाने की संपत्ति पर रह रहे कच्छी गुजराती परिवार (कच्छी ठेकेदार, जो अंग्रेजो के समय से रेल्वे का काम करते थे) के पारिवारिक विवाद का फायदा उठाकर भूमाफिया ने परिवार के एक सदस्य को गुमराह करके ने बिना कोर्ट के निर्णय के संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया।

जानकारी के अनुसार, बांदीकुई में अंग्रेजों के जमाने से कब्जे में रही कई पैतृक संपत्तियों को भूमाफिया ने निशाना बनाया है। इन संपत्तियों पर पहले से अदालत में मामले

चल रहे हैं, लेकिन भूमाफिया अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना ही इन जमीनों को खुर्द-बुर्द करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपनी रसूख से कोर्ट स्टे हटाकर करोड़ों का सौदा किया है।

भूमाफिया का दबदबा

भूमाफिया ने अदालत से स्टे हटवाकर करोड़ों रुपये में इन कृषि भूमि संपत्तियों का सौदा कर लिया। और अब वहाँ कॉलोनी बसा रहे है, इन भूमाफिया की नज़र में न केवल निजी संपत्तियां बल्कि सरकारी जमीनें भी रही हैं। परिवार और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं है। जबरदस्ती परिवार वालों पर दबाव बनाकर मकान खाली करवाने की कई बार कोशिश की गई।

परिवार के एक सदस्य ने अपना नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, ÷जब परिवार में ही खोटा सिक्का पैदा हो जाए और परिवार के सदस्यों के साथ गद्दारी करे और भूमाफिया से मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? जब से बांदीकुई कोर्ट में केस चल रहा है इस दौरान परिवार के दस लोग स्वर्ग सिधार गए है ! कुछ परिवार बांदीकुई से पहले भी पलायन कर चुके हैं। कोर्ट में सिर्फ तारीखें चल रही हैं। अजमेर और जयपुर में केस लंबित हैं। यदि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जान से मारने की धमकियां तक मिलती हैं।

बिना बेचान के कॉलोनियां और काला धन का घोटाला

परिवार के सदस्य ने बताया कि कोर्ट के निर्णय के बिना सौदा करके करोड़ों रुपये की कॉलोनी बसाना स्थानीय राजनेता और प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। बाँदीकुई में इस पैतृक जमीन को हाईवे तक जोड़ने के लिए सवाई चक जमीन में से 15 फीट का रास्ता स्थानीय डस। की अनुशंसा पर स्वीकृत करवाया है । अभी हाल में हुई जमीन के सौदे में करोड़ों के काले धन का लेन-देन भी हुआ है। सरकार को बांदीकुई की सभी जमीन का सर्वे करवाना चाहिए, यह देश में बड़ा जमीन घोटाले के रूप में आएगा, जिसमे सरकार का भी करोडो का राजस्व नुकसान हुआ है ! बिना वैध दस्तावेजों के कॉलोनियां बसा कर कब्जा किया गया। इस पूरे मामले में स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बांदीकुई शहर में ऐसी कई कॉलोनियां बसाई गई हैं, जो बिना वैध दस्तावेजों के ही बेच दी गईं या उनके भूखंडों पर कब्जा कर लिया गया।

सरकार और प्रशासन पर सवाल

इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।

क्या है समाधान?

सरकारी जांचरू प्रशासन को इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय अदालतों में तेजीरू लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। ऐसी विवादित जमीन खरीद पर रोक लगाए ! जन जागरूकतारू लोगों को अपनी संपत्तियों के दस्तावेज सुरक्षित रखने और किसी भी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हें जानकारी रहे कि वो विवादित जमीन पर प्लाट खरीद रहे है । बांदीकुई में जमीनों से जुड़ा यह विवाद सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह मामला और गंभीर रूप ले सकता है।

पांच दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हुआ शानदार समापन

जयपुर। गुलाबी नगर में चल रहे जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (जिफ) 2025 का 21 जनवरी को भव्य समापन हुआ। पांच दिनों तक चले इस आयोजन ने जयपुर, राजस्थान और भारत को विश्व सिनेमा समुदाय से जोड़ने की एक नई मिसाल कायम की। देश-विदेश से आए 650 से अधिक फिल्ममेकर्स ने जयपुर में शिरकत की और स्थानीय फिल्म प्रेमियों के साथ अपनी कहानियां और अनुभव साझा किए। यह फेस्टिवल न केवल सिनेमा का जश्न था, बल्कि राजस्थान और भारत में फिल्म उद्योग के विकास का एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित हुआ।

फेस्टिवल की शुरुआत 17 जनवरी को म्यूजिकल रेड कार्पेट से हुई, और समापन 21 जनवरी को 62 फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ हुआ। पहले दिन फेस्टिवल इनोग्रषन तथा अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। दूसरे दिन से विभिन्न स्क्रीन पर सलेक्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुइं इस बार फेस्टिवल में सिनेमा प्रेमियों ने 48 देशों की 240 फिल्मों का लुत्फ उठाया और हर स्क्रीनिंग पर अद्भुत उत्साह देखने को मिला। फेस्टिवल में रोज विभिन्न वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित किए गए। जिनमें फिल्म तथा फिल्मों से जुड़ी बारीकियों पर कई सेशन्स आयोजित किये गए। इसमें फिल्मों से जुड़े कई विषयों पर चर्चाएं भी हुई जिनमें फिल्म निर्माता व निर्देशकों ने हिस्सा लिया। जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ अनेक रोचक चर्चा सत्र, वर्कशॉप, सेमिनार्स और बहुचर्चित इन्टरनेशनल को-प्रोडक्शन मीट का आयोजन का आयोजन किया गया जिसमें देशी-विदेषी फिल्मकारों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल ने न केवल सिनेमा को बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और पर्यटन को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। जिफके कारण राज्य सरकार को लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, वहीं आयोजन स्थल के आसपास के सभी होटल अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स से भर गए। यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ।

जिफका यह आयोजन न केवल सिनेमा के प्रति उत्साह को बढ़ावा देने वाला था, बल्कि राजस्थान को विश्व सिनेमा के मानचित्र पर स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। जिफ के

माध्यम से भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के बीच पुल बनने की यह परंपरा अगले साल जनवरी 2026 में फिर जारी रहेगी।

महाकुम्भ नगर में हुआ 76वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन

नई दिल्ली। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य-भव्य महाकुम्भ के दौरान 76वें गणतंत्र दिवस का विशेष आयोजन हुआ। आस्था और भक्ति के इस अद्वितीय महापर्व में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम में डुबकी लगाने पहुंची। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर महाकुम्भ मेला क्षेत्र और अखाड़ों में भारतीयता के रंग में रंगा एक अद्वितीय दृश्य देखने को मिला। साधु-संतों के अखाड़ों से लेकर कल्पवासियों के कैम्प और सरकारी विभागों के अस्थाई मेला आफिस तक सभी जगह ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। इस दिन संगम तट पर, जहां आस्था के स्नान के लिये आते हैं, वहीं राष्ट्रप्रेम और एकता का संदेश भी गूंज रहा था। महाकुम्भ मेला क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज की शान में तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रध्वज को सम्मानित किया गया। विभिन्न स्थानों पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह ने महाकुम्भ नगर को एक नई ऊर्जा से भर दिया।

इस विशेष अवसर पर समाज कल्याण विभाग के शिविर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां मिर्जापुर के वृद्धाश्रम से आई 70 वर्षीय मुन्नी देवी ने ध्वजारोहण किया। यह दृश्य न केवल भावनात्मक था, बल्कि यह दर्शाता था कि महाकुम्भ न केवल आस्था का बल्कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता का महापर्व है। मुन्नी देवी जैसे वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति ने इस दिन को और भी खास बना दिया। महाकुंभनगर में वरिष्ठजनों की उपस्थिति ने गणतंत्र दिवस के आयोजन को गर्व से भर दिया। साथ ही सरकार द्वारा महाकुम्भ मेला क्षेत्र में बनाए गए विशेष शिविर और वृद्धाश्रम में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। यह शिविर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है, ताकि वे महाकुम्भ में आकर बिना किसी परेशानी के संगम में पवित्र स्नान कर सकें।

कार्यक्रम के दौरान महाकुंभनगर के विभिन्न अखाड़ों, सरकारी कार्यलयों और समाजसेवी संस्थानों के कैम्प में राष्ट्रभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। योगाभ्यास ने इस महाकुम्भ के आयोजन को शारीरिक और मानसिक रूप से भी ऊर्जावान बना दिया। महाकुम्भ में गणतंत्र दिवस का यह आयोजन न केवल राष्ट्रीयता और एकता का प्रतीक बना, बल्कि यह साबित करता है कि महाकुम्भ केवल धार्मिक आस्था का आयोजन नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को एक साथ जोड़ने का एक अद्वितीय अवसर भी है। इस आयोजन ने न केवल एकात्मता का संदेश दिया, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि कैसे एक समर्पित समाज अपने बुजुर्गों की गरिमा और उनके अधिकारों का सम्मान करता है।

संपादकीय

भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा?

आज भारत के संदर्भ में यह सपना देखा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के बल पर वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। परंतु, सकल घरेलू उत्पाद में औसतन लगभग 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ क्या भारत वास्तव में वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा अथवा भारत को अभी भी कई प्रकार के सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी देश को अपनी आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए कई प्रकार के सुधार कार्यक्रम लागू करने होते हैं। भारत ने वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, एक लम्बे अंतराल के पश्चात देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को वर्ष 1991 में प्रारम्भ किया। जबकि इस समय तक अमेरिका एवं कई यूरोपीय देश विकसित राष्ट्र बन चुके थे एवं चीन ने तो आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को वर्ष 1980 में ही लागू कर दिया था तथा अपनी वार्षिक आर्थिक विकास दर को दहाई के आंकड़े के भी पार ले गया था। भारत इस मामले में बहुत पिछड़ चुका था। राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1985-86 में भारतीय संसद में एक सुधारवादी बजट पेश जरूर किया था परंतु वे इन कार्यक्रमों को बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए। परंतु, वर्ष 1991 में श्री नरसिम्हा राव सरकार ने देश में लाइसेन्स राज को समाप्त कर सुधारवादी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। इसके पूर्व निजी क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त नहीं था और केवल पब्लिक सेक्टर के दम पर ही भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था। तात्कालीन केंद्र सरकार द्वारा समाजवादी नीतियों को अपनाए जाने के चलते भारत में सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करने में बहुत अधिक देर कर दी गई थी। वर्ष 1947 में भारत के राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात बड़े उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पेट्रोलियम रिफाइनरी, मशीनरी एवं तकनीकी उद्योगों पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया जबकि आज यह समस्त उद्योग देश में अत्यधिक सफल होकर देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं।वर्तमान में केंद्र सरकार 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हाल ही के वर्षों में लागू किए गए सुधार कार्यक्रमों में शामिल हैं- वस्तु एवं सेवा कर बिल, ऋणशोधना क्षमता बिल, दिवालियापन बिल, आदि। श्रम कोड को भारतीय संसद ने पास कर दिया है परंतु देश में लागू किया जाना शेष है, कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण बिल पर कार्य चालू है। ईज आफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है और आज विभिन्न प्राजेक्ट्स को समय पर स्वीकृती मिल जाती है। भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित अवस्था में आ चुका है। भारत को विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में से निकालकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ले आया गया है। फिर भी, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल 7 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर काफी नहीं है।वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.2 प्रतिशत की रही है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,300 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है। किसी भी देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तभी शामिल किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन किए अर्पित

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (शहीद दिवस) पर प्रातः शासन सचिवालय पहुंचे। शर्मा ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शर्मा ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तेने कहिये, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो, श्री राम जय राम, तू ही है तो सहारा' सुने। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सहित अन्य मंत्रीगण, मुख्य सचिव सुधांश पंत, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी-कर्मचारियों ने भी मौन रखकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने कहा कि यातायात नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से प्रदेश में व्यापक स्तर पर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के व्यापक उपाय, नवाचारों एवं परिवहन क्षेत्र में डिजिटल समाधानों पर संकल्पित होकर कार्य कर रही है, जिसके भविष्य में सुखद परिणाम नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित हो सकेगा।

उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा 30 जनवरी को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा में परवाह (केयर) की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स के सुधार और रेस्ट एरिया के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा, जिससे यात्रा और भी सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। उन्होंने आह्वान किया कि आवागमन के दौरान अन्य चालकों और राहगीरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, ताकि किसी को भी असुविधा न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में यह सड़क सुरक्षा माह यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने, सड़क हादसों में कमी लाने एवं जन-जन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरुक करने में मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले उन्होंने सभी को सड़क सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई।

शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा शुचि त्यागी ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, विभाग यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के दौरान जयपुर शहर के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर (प्रथम) राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 20 हजार से अधिक बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियानों के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस माह के दौरान वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर कठोर कार्रवाई की गई। समारोह में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले सड़क सुरक्षा प्रहरियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया कर्मियों, कार्मिकों तथा भांकरोटा सड़क हादसे में बचाव कार्य कर अदम्य साहस का परिचय देकर मिसाल कायम करने वाले आमजन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर (खण्डपीठ जयपुर) में 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने राष्ट्रीय धुन के साथ राजस्थान पुलिस के जवानों की सलामी ली। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण, पूर्व न्यायाधीशगण, न्यायविद्, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता तथा न्यायिक सेवा से जुड़े कार्मिक उपस्थित रहे।

सांभर महोत्सव 2025 में दो लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक हुए शामिल

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों एवं निर्देशन से साकार सांभर महोत्सव 2025 में इस बार लगभग 2 लाख से अधिक देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन ने सांभर को पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का यह उत्सव 24 जनवरी से 28 जनवरी तक चला। महोत्सव में आगन्तुक पर्यटकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और रोमांचकारी पर्यटन के अनुभव हुए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। यह विशिष्ट एवं अविस्मरणीय, मनमोहक लोक उत्सव ने निश्चित ही सांभर को पर्यटन के क्षेत्र में एक नये सितारे के रूप में पहचान दी है, जो कि पर्यटकों के लिए लम्बे समय तक अचंभे और आकर्षण केन्द्र बना रहेगा। सांभर महोत्सव अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया।

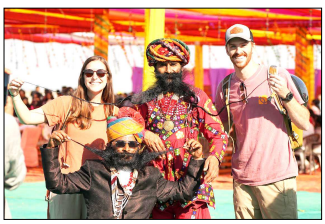

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांभर महोत्सव 24 से 28 जनवरी तक सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि सांभर की साल्ट लेक अब प्री-वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो रही है। झपोक, सांभर सॉल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर और मेला ग्राउंड पर इस महोत्सव के दौरान कई भव्य आयोजन हुए, जिसमें पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग उमंग और उत्साह के साथ शामिल हुए।

उत्सव के आकर्षण

पूर्व विधायक फुलेरा विधानसभा निर्मल कुमावत और अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर 24 जनवरी को सांभर महोत्सव 2025 की विधिवत शुभारम्भ किया गया। जिसमें संध्या के समय देवयानी तीर्थ सरोवर पर दीपोत्सव और महाआरती की गई। महोत्सव में सैलानी और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांच के अनुभवों से रूबरू हुए। इस दौरान राजस्थानी कला एवं शिल्प स्टॉल और फोटोग्राफी का प्रदर्शन हुआ। विभिन्न डिजाइन और रंगों की फैंसी पतंगें आकाश में उड़ाई गई। पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी और एटीवी राइड्स जैसी रोमांचक गतिविधियां आयोजित हुई। प्रकृति प्रेमियों के लिए पक्षी अवलोकन और साल्ट लेक भ्रमण का अनुभव अद्वितीय रहा। दीपोत्सव और महाआरती ने सांस्कृतिक संध्या को और खास बनाया। लोक कलाकारों की मनमोहक स्ट्रीट परफॉर्मेंस ने पर्यटकों को लुभाया। सांभर टाउन हेरिटेज वॉक, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं जैसी विशेष गतिविधियां आयोजित हुई। घुड़सवारी, ऊँट सवारी और ऊँट गाड़ी की सवारी ने भी पर्यटकों को खासा आकर्षित किया। सितारों का अवलोकन और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पर्यटकों को नमक प्रसंस्करण दूर ने भी लुभाया। 28 जनवरी को समारोह का समापन हुआ।

भारत के एप्पल मैन हरिमन शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के दूरदर्शी किसान हरिमन शर्मा को भारतीय कृषि में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एचआरएमएन-99 नामक एक अभिनव, स्व-परागण (पौधे के परागकण उसी पौधे के किसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं) युक्त और कम ठंड में उपजने वाली सेब की किस्म विकसित की है, जिसने देश में सेब की बागवानी में क्रांति ला दी है। इससे भौगोलिक दृष्टि से बागवानी व्यापक हो गई है और रसदार पौष्टिक सेब की यह किस्म लोगों तक पहुंच गई है। व्यावसायिक सेब की अन्य किस्मों को समशीतोष्ण जलवायु और लंबे समय तक शीतकालीन मौसम की आवश्यकता होती है, पर इसके विपरीत एचआरएमएन-99 की बागवानी उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है, जहां गर्मियों में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे अब उन क्षेत्रों में भी सेब की खेती संभव हो सकती है, जहां पहले इसे अव्यवहारिक माना जाता था।

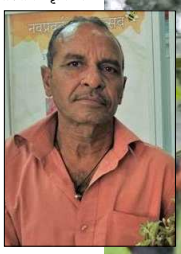

बचपन में ही अनाथ हो गये हरिमन शर्मा का बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) स्थित छोटे से गांव पनियाला की पहाड़ी गलियों से राष्ट्रपति भवन के भव्य कक्ष तक का सफर कृषक समुदाय के साथ ही देश के छात्रों, शोधकर्ताओं और बागवानी करने वालों के लिए काफी प्रेरणादायक है। तमाम मुश्किलों के बावजूद शर्मा ने मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की और खेती-किसानी और फल उपजाने के प्रति अपना जुनून बनाए रखा। एचआरएमएन-99 सेब किस्म की उपज की कहानी 1998 में तब शुरू हुई जब हरिमन शर्मा ने अपने घर के पिछले हिस्से में घर में इस्तेमाल किये गये सेब के कुछ बीज लगा दिये। इनमें से एक बीज उल्लेखनीय रूप से अगले वर्ष अंकुरित हो गया और 1,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित पनियाला की गर्म जलवायु के बावजूद 2001 में पौधे ने फल दिये। शर्मा ने यह देखते हुए सावधानीपूर्वक मातृ पौधे की देखभाल की और ग्राफ्टिंग द्वारा कई पौधे लगाए और अंततः सेब का एक समृद्ध बाग स्थापित कर लिया। अगले दशक में, उन्होंने विभिन्न कलमों में ग्राफ्टिंग तकनीकों का प्रयोग कर सेब की अभिनव किस्म को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। समान जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में इस सफलता को दोहराने के प्रयासों के बावजूद शुरुआत में उनके काम पर कृषि और वैज्ञानिक समुदायों का अधिक ध्यान नहीं गया।

वर्ष 2012 में, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ)-भारत ने इसका पता लगाया। एनआईएफ ने सेब की किस्म की विशिष्टता सत्यापित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि विभागों, किसानों और देश भर के स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आणविक अध्ययन, फल गुणवत्ता परीक्षण और बहु-स्थान परीक्षणों की सुविधा प्रदान कर इसकी विशिष्टता प्रमाणन में सहयोग दिया। इन सहयोगी प्रयासों से, सेब की यह किस्म 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गई। इनमें बिहार, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा और नगर हवेली, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। साथ ही इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भी लगाया गया है। एनआईएफ ने इसका पंजीकरण नई दिल्ली के पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण में करने में सहायता प्रदान की।

अपने अभिनव प्रयास के लिए हरिमन शर्मा को वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक ग्रासरूट इनोवेशन और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कारों के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा भी शर्मा कई पुरस्कारों से सम्मानित किये गये हैं। इनमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान पुरस्कार (2016), आईएआरआई फेलो पुरस्कार (2017), डीडीजी, आईसीएआर द्वारा किसान वैज्ञानिक उपाधि (2017), राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार (2018), राष्ट्रीय कृषक सम्राट सम्मान (2018) जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार (2019) और कई राज्य और केंद्र सरकार के पुरस्कार शामिल हैं। हरिमन शर्मा ने नवंबर 2023 में मलेशिया में आयोजित चौथे आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम (एआईजीआईएफ) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। एचआरएमएन-99 सेब की किस्म की विशेषता इसकी धारीदार लाल-पीली त्वचा, मुलायम और रसदार गूदा तथा प्रति पौधा सालाना 75 किलोग्राम तक फल देने की क्षमता है। सेब की इस प्रजाति की बागवानी से देश में हजारों किसान लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन ने इसकी व्यावसायिक बागवानी को सहयोग देने तथा बाग लगाने और राज्य कृषि विभागों तथा भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के उत्तर पूर्वी परिषद के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस किस्म को रोपने के प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इस किस्म के एक लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं, जिससे किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिला है।

हरिमन शर्मा के विशिष्ट नवाचार से भारत में सेब की बागवानी में उल्लेखनीय बदलाव आया है, साथ ही इसने बड़े पैमाने पर किसानों को अतिरिक्त आय और पोषण के बेहतर स्रोत अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उनके प्रयासों से कभी अमीरों का आहार माना जाने वाला सेब अब आम आदमी की पहुंच में आ गया है। पद्म श्री पुरस्कार द्वारा हरिमन शर्मा के प्रयासों को मान्यता मिलना, राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित स्थायी आजीविका सृजन में जमीनी स्तर के नवाचारों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है।

राजस्थान में आईटी सेक्टर के विकास और विस्तार पर हुई चर्चा

जयपुर। राजस्थान में आईटी उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से आईटी वॉयस और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में 28 जनवरी को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित हुआ जिसमें आईटी क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोगों और संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के आगामी बजट 2025-26 के लिए सुझाव देना और आईटी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए विचार-विमर्श करना था। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने आईटी उद्योग की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की।

राज्य टेंडरों में स्थानीय आईटी व्यवसायों को प्राथमिकता

डॉ. के.एल. जैन, अध्यक्ष, आरसीसीआई ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार के टेंडरों में 20-30 प्रतिषत हिस्सा राजस्थान के स्थानीय आईटी व्यवसायों के लिए आरक्षित होना चाहिए। उन्होंने इसे स्थानीय व्यवसायों और राज्य की आर्थिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

साइबर और एआई लैब की स्थापना

डॉ. तरुण टांक (सीईओ एण्ड चीफ एडिटर, आईटी वॉयस) ने साइबर और एआई लैब्स की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये लैब्स न केवल छात्रों के कौशल को विकसित करेंगी, बल्कि स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान करेंगी।

डेटा सेंटर और क्लाउड कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार

चांदनी जग्गा (चेयरपर्सन, आरसीसीआई लॅम्, एडिशनल सेक्रेटरी, आरसीसीआई) ने डेटा सेंटर और क्लाउड कंपनियों को राजस्थान में लाने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च लागत और पुरानी नीतियों के कारण कंपनियां राजस्थान छोड़कर अन्य राज्यों का रुख कर रही हैं।

आईटी सेवा उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता

ललित चैधरी (अध्यक्ष, जेसीटीए) ने कहा कि आईटी सेवा उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी फाइलिंग और टर्नओवर के आधार पर ऋण योजनाएं लागू की जाएं, ताकि इन उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय समर्थन मिल सके।

आईटी क्लस्टर और जमीन आवंटन की आवश्यकता

पंकज गुप्ता (इंडियन एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) ने राजस्थान में आईटी क्लस्टर और जमीन आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आईटी क्लस्टर से वितरण, निर्यात और सेवा उद्योगों को एक संगठित ढांचा मिलेगा, जो राजस्थान को एक सशक्त आईटी हब बनाने में सहायक होगा।

आईटी पार्क के माध्यम से प्रतिभा को रोकना

डॉ. के.एल. जैन और ललित चैधरी ने राजस्थान में आईटी पार्क स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में प्रतिभाशाली पेशेवरों को बनाए रखने और राजस्थान को आईटी हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

आईटी शिक्षा प्रणाली में सुधार

ललित चैधरी (अध्यक्ष, जेसीटीए) ने कहा कि आईटी शिक्षा प्रणाली को उद्योग की जरूरतों के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता है। उन्होंने व्यवहारिक कौशल और अप-स्किलिंग को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया।

उद्योग और शिक्षा के बीच सेतु का निर्माण

दिनेश छाबड़ा (पीआरओ, जेसीटीए और पूर्व उपाध्यक्ष, आरसीटीए) ने उद्योग और शिक्षा के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को उनके कौशल के अनुसार स्थानीय अवसर मिलें और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता न हो।

इस कार्यक्रम में डॉ. के.एल. जैन (अध्यक्ष, आरसीसीआई), डॉ. तरुण टांक (सीईओ और चीफ एडिटर, आईटी वॉयस), चांदनी जग्गा (चेयरपर्सन, आरसीसीआई लॅम्, एडिशनल सेक्रेटरी, आरसीसीआई), ललित चैधरी (अध्यक्ष, जेसीटीए), अरविंद बत्रा (चेयरपर्सन, रोटरी बिजनेस), पंकज गुप्ता (इंडियन एमएसएमई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), दिनेश छाबड़ा (पीआरओ, जेसीटीए और पूर्व उपाध्यक्ष, आरसीटीए), विघ्नेश टांक (राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान), अशोक टांक (राष्ट्रीय और स्थानीय वितरकों के प्रतिनिधि), शरद राठी (प्रतिनिधि, त्ज्म्ळ), सचिन खंडेलवाल (आईएसपी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान), मिहिर शर्मा (पूर्व अध्यक्ष, आरसीटीए) और अन्य कई प्रमुख प्रतिनिधि, एसोसिएशन एवं आईटी कंपनियों के प्रमुख व्यक्ति शामिल रहें

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम को आईटी वॉयस और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सफलतापूर्वक आयोजित किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि राजस्थान में आईटी सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समूह ने यह भी निर्णय लिया कि चर्चा में दिए गए सुझावों के साथ वे सरकार से संपर्क करेंगे, ताकि आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जा सके।

iTVoice® all things tech.

India's Premier IT Magazine & First Daily Tech News OTT

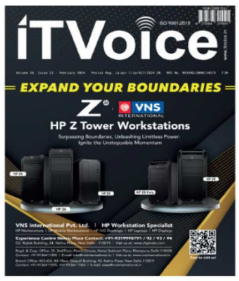

Magazines & Newspapers

Highest Digital Presence

www.itvoice.in

Daily Tech News & Podcasts

Contact for Print & Digital Marketing

+91 141 4014911
info@itvoice.in

ICPL
www.icpljpr.com

Professional IT Support

Domain & Hosting
Web Development
Customized Software Solution
Web Operation
Client / Server Management
Network Maintenance
Service Desk Support
Customized IT Support Services
Dealing in all Major Brands

Informatic Computech Private Limited

Jaipur - Rajasthan (Ph.) +91-141-2280510 md@icpljpr.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com